

## पश्चिम एशिया: अत्यधिक सैन्यीकृत क्षेत्र

यह एडिटरियल 25/04/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Tensions grows in west asia, a heavily militarised region”](#) लेख पर आधारित है। इसमें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम एशिया वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है, जहाँ विश्व के शीर्ष 10 हथियार आयातक देशों में से चार अवस्थित हैं।

### प्रलमिस के लिये:

[स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट](#), [ईरान](#), [इज़राइल](#), [मध्य पूर्व](#), [इस्लामी क्रांति, 1979](#), [गाजा पट्टी](#), [लाल सागर संकट](#), [इजरायली वायु रक्षा प्रणाली](#), ['टू स्टेट सॉल्यूशन'](#), [खाड़ी सहयोग परिषद](#), [यूरोपीय संघ](#), [संयुक्त राष्ट्र](#), [संयुक्त व्यापक कार्य योजना \(JCPOA\)](#)।

### मेन्स के लिये:

पश्चिम एशिया में हाल के संघर्ष का विश्व के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव।

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है। यह वह क्षेत्र है जो सैन्यीकरण पर अत्यधिक निर्भर है और वैश्विक हथियारों के आयात में 30% हस्तिसेदारी रखता है। वैश्विक ऊर्जा उपभोग के लिये नषिकर्षण संसाधनों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता होने के बावजूद, पश्चिम एशिया विभिन्न संघर्षों के कारण बढ़ती अस्थिरता का सामना कर रहा है।

**इज़राइल-गाजा संघर्ष**, ईरान एवं इज़राइल के बीच शत्रुता और लेबनान एवं यमन के ईरान समर्थित मलिशिया द्वारा जारी हमले तनाव बढ़ा रहे हैं।

**'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट'** के अनुसार, पश्चिम एशिया वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है और विश्व के शीर्ष 10 हथियार आयातकों में से चार यहीं स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता है। इस सैन्यीकरण ने पश्चिम एशिया को संभावित 'बारूद के ढेर' पर बठा रखा है।

## पश्चिम एशिया में हाल की अशांतिके पीछे के कारण:

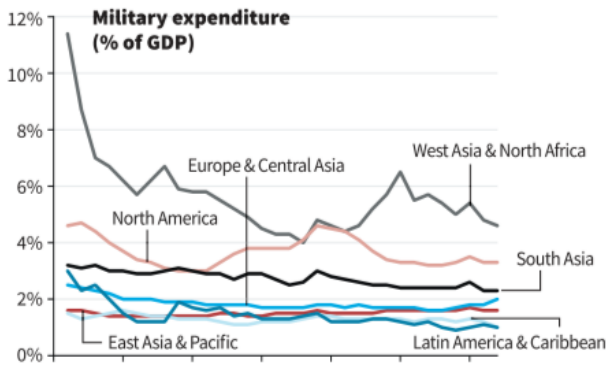
- इज़राइल ने गाजा के वरिद्ध युद्ध छेड़ दिया, जबकि ईरान समर्थित लेबनानी शिया समूह हजिबुल्लाह ने फलिसितीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शीबा फार्म्स (Shebaa Farms) में इज़राइली सैन्य बलों पर रॉकेट दागे। शीबा फार्म्स एक इज़राइल-नियंत्रित क्षेत्र है, जिस पर लेबनान अपना दावा करता है।
- इजरायल की अंधाधुंध बमबारी से असंतुष्ट अरब देशों ने यहूदी राज्य पर दबाव बनाने के लिये कूटनीतिके रास्ते आजमाए।
  - ईरान समर्थित मलिशिया ने भी इज़राइल के खिलाफ नए मोर्चे खोल दिए।
- यमन की शिया मलिशिया हूती (Houthis) ने फलिसितीनियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए नवंबर माह के मध्य में लाल सागर में वाणज्यिक जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया।
  - उन्होंने कई शिपिंग दिगिजों को लाल सागर में अपना परिचालन नलिंबित करने के लिये विविश कथि। लाल सागर स्वेज नहर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य के माध्यम से भूमध्य सागर को अरब सागर (और हृदि महासागर) से जोड़ता है।
- इज़राइल ने सीरिया और लेबनान के अंदर कई हमले कथि हैं, जिसमें हमास, हजिबुल्लाह और ईरान के सैन्य कमांडर मारे गए हैं।
- ईरान ने 16 जनवरी को इराक के कुरदस्तान, सीरिया और पाकस्तान में हमले कथि, जिसमें मोसाद ऑपरेशनल सेंटर और सुन्नी इस्लामी आतंकवादियों को नशाना बनाने का दावा कथि गया।
- सकल घरेलू उत्पाद के हस्तिसे के रूप में पश्चिम एशिया का सैन्य परवियय उच्च बना हुआ है, जहाँ सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, ओमान, कुवैत और इज़राइल जैसे देश लगातार अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्त्वपूर्ण भाग रक्षा क्षेत्र को आवंटित कर रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में सैन्य क्षेत्र में नयिोजति श्रम शक्तिका अनुपात सबसे अधिक है।

**Table 1:** United States has been the main supplier of arms to the West Asian countries. Numbers in %

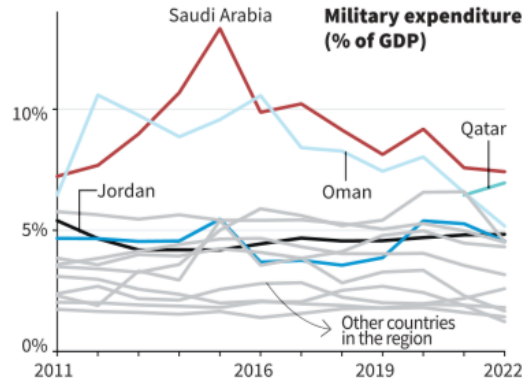
Recipient	Top supplier	Second	Third
Qatar	U.S. (49)	U.K. (26)	Italy (21)
S. Arabia	U.S. (72)	Spain (15)	France (6.5)
Turkey	Spain (51)	Germany (31)	U.S. (11)
UAE	U.S. (55)	France (27)	Turkey (12)
Israel	U.S. (53)	Germany (47)	Italy (0.6)
Kuwait	Italy (94)	U.S. (6.0)	-
Bahrain	U.S. (100)	-	-
Iran	Russia (100)	-	-

While most of these countries are sourcing their military supplies from the U.S. and Europe, Iran is entirely dependent on Russia

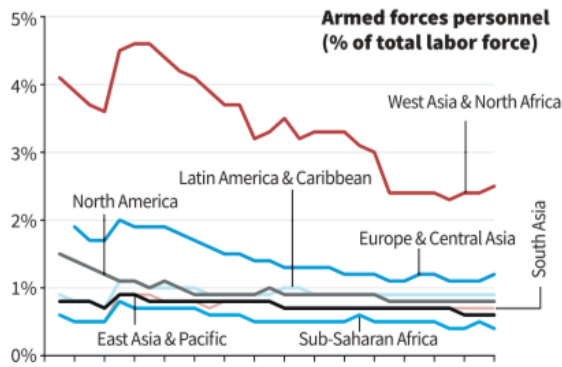
**Chart 2:** The chart shows the region-wise military expenditure as a share of their GDP. West Asia and North Africa have been consistently leading all regions for over three decades



**Chart 3:** The chart shows the military expenditure as a share of a country's GDP in the West Asian region. Saudi Arabia, Qatar and Oman lead in this measure in the region



**Chart 4:** The chart shows the share of the labour force employed in the armed forces. The West Asian and North African region leads in this measure



## पश्चिमि एशियाई संघर्ष के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव:** पश्चिमी एशिया वृहत रूप से 14वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में रहा था।
  - इस साम्राज्य ने एक सफल प्रशासनिक प्रणाली के माध्यम से विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों वाली विविध आबादी पर शासन किया।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद की प्रगत:** प्रथम विश्व युद्ध और ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद, इस भूभाग में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वजियी मति राष्ट्रों (मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस) ने स्थानीय अरब आबादी की इच्छाओं की प्रायः उपेक्षा करते हुए पूर्व ऑटोमन क्षेत्रों को आपस में बाँट लिया।
  - इससे, विशेष रूप से युद्ध के दौरान अरब समर्थन के बदले में किये गए वादों को तोड़ने के कारण, विश्वासघात और आक्रोश की भावनाएँ पैदा हुईं।
- साइक्स-पिकोट समझौता (Sykes-Picot Agreement):** यह वर्ष 1916 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच संपन्न एक अनौपचारिक संधि थी, जिसमें रूसी साम्राज्य और इटली की सहमति भी शामिल थी, ताकि ऑटोमन साम्राज्य के अंतिम विभाजन में प्रभाव एवं नियंत्रण के उनके पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों को परिभाषित किया जा सके।
  - इस समझौते ने प्रभावी रूप से अरब प्रायद्वीप के बाहर के ऑटोमन प्रांतों को ब्रिटिश और फ्रांसीसी नियंत्रण एवं प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया।
- बाल्फोर घोषणा (Balfour Declaration):** यह वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी एक सार्वजनिक वक्तव्य था, जिसमें फलिसतीन में 'यहूदी लोगों के लिये राष्ट्रीय गृहक्षेत्र' (national home for the Jewish people) की स्थापना के लिये समर्थन की घोषणा की गई थी। फलिसतीन उस समय एक ऑटोमन क्षेत्र था जहाँ एक छोटी अल्पसंख्यक यहूदी आबादी पाई जाती थी। इस घोषणा के कई दीर्घकालिक परिणाम सामने आए।
  - इज़राइल का निर्माण:
    - वर्ष 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने फलिसतीन में 'यहूदी लोगों के लिये राष्ट्रीय गृहक्षेत्र' की स्थापना के लिये समर्थन व्यक्त करते हुए **बाल्फोर घोषणा** जारी की।
    - द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद, वर्ष 1947 में **संयुक्त राष्ट्र (UN)** ने एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा जहाँ फलिसतीन को अलग-अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित किया जाना था और यरूशलेम को एक अंतरराष्ट्रीय नगर की स्थिति प्रदान की जानी थी।
    - वर्ष 1948 में **इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा** कर दी, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया।
- अरब-इज़राइल युद्ध (1948):**

- वर्ष 1948 में इज़राइल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा ने आसपास के अरब राज्यों को उस पर हमले के लिये प्रेरित किया।
- युद्ध के अंत में इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र वभाजन योजना की मूल कल्पना से लगभग 50% अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था।
- वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति:
  - वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति में शाह को उखाड़ फेंकने के बाद ईरान में एक धार्मिक राज्य की स्थापना हुई। इसके साथ ही इज़राइल के प्रति ईरान का दृष्टिकोण बदल गया और उसे फलिसितीनी भूमि पर कब्ज़ा करने वाले या 'ओक्यूपायर' (occupier) के रूप में देखा जाने लगा।
  - ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी (Ayatollah Khomeini) ने इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले पक्षों के रूप में चिह्नित करते हुए इन्हें क्रमशः 'छोटा शैतान' और 'बड़ा शैतान' पुकारा।
- वर्ष 1979 के बाद एक 'छाया युद्ध' (Shadow War):
  - इसके परिणामस्वरूप देशों के संबंध और बगिड़ गए। उल्लेखनीय है कि इज़राइल और ईरान कभी भी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव में संलग्न नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों ने छद्म आभिक्रताओं (proxies) और सीमित रणनीतिक हमलों के माध्यम से एक दूसरे को क्षति पहुँचाने का प्रयास किया है।
  - वर्ष 2010 के दशक की शुरुआत में इज़राइल ने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिये उसके कई प्रतिष्ठानों और परमाणु वैज्ञानिकों को नशाना बनाया।
  - माना जाता है कि वर्ष 2010 में अमेरिका और इज़राइल द्वारा एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर वायरस 'स्टक्सनेट' (Stuxnet) विकसित किया था। इसका उद्देश्य ईरान के नैटानज़ (Natanz) परमाणु स्थल पर अवस्थित यूरेनियम संवर्द्धन प्रतिष्ठान पर हमला करना था। इसे किसी औद्योगिक मशीनरी पर पहले सार्वजनिक रूप से ज्ञात साइबर हमले के रूप में देखा गया।
  - दूसरी ओर, ईरान को इस क्षेत्र में कई आतंकवादी समूहों—जैसे लेबनान में हजिबुल्लाह और गाज़ा पट्टी में हम्मास, के वित्तपोषण और समर्थन के लिये ज़िम्मेदार माना जाता है जो इज़राइल और अमेरिका वरिधी समूह हैं।
- हाल के घटनाक्रम:
  - इज़राइल पर ईरान का पूर्ण पैमाने का सैन्य हमला त था गाज़ा में इज़राइल की नरिंतर कार्रवाई ने इस क्षेत्र की अस्थिरता को और बढ़ाया है।
  - यमन के गृहयुद्ध, लेबनान के राजनीतिक संकट, सीरिया के गृहयुद्ध और तुर्की-साइप्रस संघर्ष सहित विभिन्न संघर्षों की नरिंतरता अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को बढ़ा रही है।

## प्रमुख हतिधारक कौन हैं और उनके भिन्न उद्देश्य क्या हैं?

- **इज़राइल:** उसके उद्देश्यों में हम्मास का अंत करना, बंधकों को रहा कराना और अपनी सुरक्षा के लिये खतरों को बेअसर करना शामिल हैं।
  - गाज़ा में इसकी सैन्य कार्रवाई और अन्य क्षेत्रों में हमले इसी उद्देश्य को परलिक्षति करते हैं।
- **हम्मास:** गाज़ा एवं वेस्ट बैंक में इज़राइल की नीतियों और कार्यों को चुनौती देने की इच्छा रखता है।
  - एक फलिसितीनी इस्लामी राजनीतिक संगठन और आतंकी समूह के रूप में यह इज़राइल के साथ लंबे समय से संघर्ष में शामिल रहा है।
- **ईरान:** यह पश्चिम एशिया में विभिन्न इज़राइल वरिधी गैर-राज्य अभिक्रताओं (जैसे हम्मास, इस्लामिक जहाद, हजिबुल्लाह, हूती या इराक एवं सीरिया के शिया मल्लिशिया) का समर्थन करता है।
  - ईरान का लक्ष्य भूभाग में अपना प्रभाव बढ़ाना है, जहाँ वह प्रायः अमेरिकी और इज़राइली हतियों का वरिध करता है।
- **हजिबुल्लाह और अन्य मल्लिशिया:** प्रायः ईरान द्वारा समर्थित ये समूह मुख्य रूप से इज़राइल के वरिध में और फलिसितीनी हतियों के समर्थन में संघर्ष में शामिल रहे हैं।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** वह इज़राइल का समर्थन करता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और अपने हतियों की रक्षा करने की इच्छा रखता है।
  - इस भूभाग में व्यापक सैन्य उपस्थिति और कूटनीतिक पकड़ रखने वाले अमेरिका के तीन उद्देश्य हैं-
    - इज़राइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना
    - क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों और परसिपत्तियों की सुरक्षा
    - क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना
- **अन्य क्षेत्रीय अभिक्रता:** पाकस्तान जैसे देशों के इस संघर्ष में अपने रणनीतिक हति हैं, जो प्रायः धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय समीकरण से प्रभावित होते हैं।

Country	Ally/backing	Against
Israel	U.S.A	Iran, Hamas, Houthi, Hezbollah
Iran (Shia majority)	Houthi, Hamas, Hezbollah, Iran Revolutionary Guard, pro-Iran Shiiia militants in Syria and Iraq	Israel, U.S.A, Islamic State (pro-Sunni), Jaish Al-Adl (pro-Sunni)

## पश्चिम एशिया में संघर्षों का भू-राजनीतिक प्रभाव:

- **मानवीय संकट:** नरिंतर सैन्य कार्रवाइयों से, वशिष रूप से गाज़ा में, भारी संख्या में लोगों के हताहत होने और मानवीय स्थितियों के बगिड़ने का खतरा है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** दीर्घावधक संघर्ष पहले से ही अस्थिर पश्चिमि एशियाई क्षेत्र को और अस्थिर कर सकते हैं जिससे पड़ोसी देश प्रभावित हो सकते हैं। गाज़ा में इज़राइल की कार्रवाइयों के कम होने के कोई संकेत नहीं दखि रहे हैं, जिससे हजिबुललाह और हूती के हमले भी लगातार जारी हैं।
- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** प्रमुख शपिगि मार्गों (जैसे लाल सागर) और तेल आपूर्ति में व्यवधान के वैश्विक आर्थिक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- **चरमपंथ का प्रसार:** जारी संघर्ष कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकते हैं तथा चरमपंथी समूहों के उदय का कारण बन सकते हैं, जिससे क्षेत्र और अस्थिर हो सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय संबंध:** यह संघर्ष वैश्विक शक्तियों और क्षेत्रीय राज्यों के बीच राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है, जिससे शांति एवं स्थिरता के लिये अंतरराष्ट्रीय प्रयास जटलि सदिध हो सकते हैं।
- **सुरक्षा वफिलता:** पश्चिमि एशिया में पछिले संघर्षों (जहाँ प्रायः राष्ट्र-राज्य या राज्य और गैर-राज्य अभकिरता शामिल थे) के वपिरीत वर्तमान संकट व्यापक सुरक्षा वफिलता से चहिनति हो रहा है।

## भारत पर इसके संभावित प्रभाव

- **ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव:** पश्चिमि एशिया से आयातित तेल पर भारत की नरिभरता, मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति व्यवधानों के प्रति उसे संवेदनशील बनाती है।
  - पश्चिमि एशिया में ऊर्जा संसाधनों के लिये बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं तथा आपूर्ति के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ सकती है, जिससे भारत के लिये आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।
  - भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। भारत का 40% से अधिक तेल पश्चिमि एशिया से आता है।
- **भारतीय प्रवासी:** पश्चिमि एशिया में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या मौजूद है जिनके आय अर्जन पर पर इस उथल-पुथल का गंभीर असर पड़ सकता है।
  - **धन-प्रेषण (Remittances):** पश्चिमि एशिया के अनवासी भारतीय प्रति वर्ष लगभग 40 बलियन अमेरिकी डॉलर घर भेजते हैं जो देश के कुल धन-प्रेषण प्रवाह में 55% से अधिक की हसिसेदारी रखता है।
    - भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के अनुसार, भारत को प्राप्त कुल प्रेषण का 82% संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे पश्चिमि एशियाई देशों तथा यहाँ व्यापक रूप से संलग्न एवं सकरयि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त होता है।
- **व्यापार और नविश:** यूएन कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2017 से 2021 के बीच भारत के संचयी दो-तरफा माल व्यापार में ईरान और GCC सदस्य देशों की हसिसेदारी 15.3% थी।

## पश्चिमि एशिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण

- **मध्य-पूर्व कवाड (I2U2) पहल:** I2U2 (India, Israel, the U.S. and the UAE) के पीछे का वचिर यह है कि आर्थिक, प्रौद्योगिकीय एवं राजनयिक सहयोग के लिये दक्षिण एशिया, मध्य-पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका को परस्पर संबद्ध किया जाए।
- **'भेडकिल डिप्लोमेसी':** 'वैक्सिन मैत्री' भारत सरकार द्वारा पश्चिमि एशियाई देशों को COVID-19 टीके उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई एक मानवीय पहल थी।
  - वशिष रूप से सऊदी अरब और बहरीन इस पहल के लाभार्थी बने।
- **डाउनस्ट्रीम परियोजनाएँ:** भारत ने पश्चिमि एशिया के देशों को भारत के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में नविश करने के लिये आमंत्रित किया है।
  - अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन स्ट्रैटेजिकि पेट्रोलियम रज़िर्व्स लिमिटेड (ISPRL) के बीच जनवरी 2017 में तेल भंडारण एवं प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
  - यह रेखांकित करता है कि मैंगलोर कैवरन के लिये संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की आपूर्ति ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के नरिमाण में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम सदिध होगी।
- **ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी:** अबू धाबी ने लोअर ज़कुम (Lower Zakum) में भारत के ONGC के नेतृत्व वाले संघ को एक बड़ी तेल रियायत प्रदान की है।
  - वभिनिन उच्च-स्तरीय वादों और समझौतों पर नज़र रखने के लिये एक उच्च-स्तरीय मंत्रसित्रीय कार्यबल का गठन किया गया है।
- **टेक कूटनीति:** भारत पश्चिमि एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये प्रौद्योगिकीय मार्ग अपना रहा है।
  - उदाहरण के लिये, डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत की एक प्रमुख पहल RuPay कार्ड को अबू धाबी में लॉन्च किया गया है।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** भारत ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय समुदाय को एक वशिष उपहार के रूप में दुबई में पहले हदू मंदिर का उद्घाटन किया। योग, बॉलीवुड और संगीत भारत के सॉफ्ट पावर के अन्य कुछ आयाम हैं।

## संघर्ष को संबोधित करने के लिये कौन-से दृष्टिकोण प्रस्तावित किये गए हैं?

- **वार्ता और 'टू स्टेट सॉल्यूशन':** वभिनिन अंतरराष्ट्रीय अभकिरताओं ने वार्ता के माध्यम से प्राप्त **टू स्टेट सॉल्यूशन** की वकालत की है, जहाँ **इज़राइल और फलिसितीन** दो स्वतंत्र राज्यों के रूप में सह-अस्तित्व में रहेंगे।
  - समझौता वार्ता स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने, यरूशलेम की स्थिति जैसे मुद्दों का समाधान करने और दोनों पक्षों के लिये सुरक्षा गारंटी प्रदान करने पर लक्षित होगी।
  - **ओसलो समझौता (Oslo Accords):** इज़राइल और फलिसितीन लबिरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन (PLO) के बीच पूर्व की वार्ताएँ टू स्टेट सॉल्यूशन की प्राप्ति पर लक्षित रही थीं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विभिन्न शांति योजनाएँ।



- **युद्धविराम और मानवीय सहायता:** तत्काल युद्धविराम समझौते और संघर्ष से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता से पीड़ा को कम करने और राजनयिक समाधान के लिये माहौल बनाने में मदद मलि सकती है।
  - तीव्र संघर्ष की अवधि के दौरान शत्रुता को रोकने के लिये मस्िर, कतर और अन्य क्षेत्रीय अभिकर्ताओं की मध्यस्थता से अस्थायी युद्धविराम लागू कथिा गया था।
  - अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन गाज़ा और वेस्ट बैंक में प्रभावित आबादी को सहायता एवं समर्थन प्रदान करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता:** समझौता वार्ता और शांति वार्ता को सुवधाजनक बनाने के लिये तटस्थ अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों या संगठनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) की भागीदारी।
- **मुख्य मुद्दों को संबोधित करना:** संघर्ष के मूल कारणों—जैसे भूमि विवाद, संसाधनों तक पहुँच और शरणार्थियों के अधिकारों को संबोधित करना दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे सकता है।
- **लोगों के परस्पर संपर्क संबंधी पहल:** विश्वास और समझ के नरिमाण के लिये ज़मीनी स्तर पर इज़राइलियों और फलिसितीनियों के बीच संवाद एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  - 'सीड्स ऑफ पीस' (Seeds of Peace) और 'वनवॉइस' (OneVoice) जैसे संगठन इज़राइल और फलिसितीन के युवाओं के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।
  - व्यापार, शक्तिषा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में इज़राइल-फलिसितीन संयुक्त उद्यम की स्थापना करना जो सहयोग को बढ़ावा देंगे।
- **मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून:** यह सुनिश्चित करना कि दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार मानकों का सम्मान करें तथा उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराएँ।
  - अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) द्वारा क्षेत्र में कथित युद्ध अपराधों और मानवाधिकार हनन की जाँच की जा रही है।
  - संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में अवैध बस्तियों की नदिा की गई तथा अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान कथिा गया।
- **क्षेत्रीय सहयोग:** एक अधिकि स्थिर वातावरण के नरिमाण के लिये शांति प्रयासों में क्षेत्रीय हतिधारकों और पड़ोसी देशों को शामिल कथिा जाना चाहिये।
  - अरब शांति पहल (Arab Peace Initiative), जो फलिसितीनियों के साथ एक व्यापक शांति समझौते के बदले में इज़राइल और अरब राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की पेशकश करती है।
  - मध्य-पूर्व में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय शखिर सम्मेलनों और पहलों का आयोजन करना।
- **आर्थिक वकिसा:** इज़राइल और फलिसितीन दोनों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और अवसर पैदा करने के लिये क्षेत्र में आर्थिक वकिसा का समर्थन करना।
  - फलिसितीन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी (PIPA) और अन्य संगठन वेस्ट बैंक एवं गाज़ा में आर्थिक वकिसा को प्रोत्साहित करने के लिये कार्य कर रहे हैं।
  - आधारभूत संरचना और आर्थिक वकिसा परियोजनाओं के लिये धन जुटाने हेतु अंतरराष्ट्रीय दाता सम्मेलनों का आयोजन।
- **सुरक्षा उपाय:** इज़राइल और फलिसितीन दोनों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करना, जसिमें अंतरराष्ट्रीय शांति सेनाओं की तैनाती शामिल हो सकती है।
  - संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ट्रूस सुपरवज़िन ऑर्गेनाइज़ेशन (UNTSO), युद्धविराम की नगिरानी के लिये क्षेत्र में तैनात कथिा गए हैं।
  - हसिा को कम करने के लिये सीमा सुरक्षा व्यवस्था और विश्वास-नरिमाण के उपाय।
- **शैक्षिक पहल:** समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिये दोनों पक्षों के इतहिस एवं संस्कृति के बारे में शक्तिषा और जागरूकता को बढ़ावा देना।

- ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम जो समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि इजराइल में हैंड इन हैंड बाई-लगुअल स्कूल।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान पहल और संयुक्त कला-संबंधी परियोजनाएँ।

## नष्िकरष

इस बात की संभावना नहीं दखती कि सीरिया, यमन और मध्य-पूरव के अन्य हसिसों में जारी संघरष आसानी से समाप्त हो जाएँगे। सभी पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने के लयि शरमशील राजनीतिक कुशलता की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि पश्चमि एशया शांति योजना जैसी पहले भी अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में स्व-हतिकारी ही हैं, क्योंकि वे दूसरे पक्ष की पूरी तरह से उपेक्षा कर केवल एक पक्ष को लाभ पहुँचाती हैं।

**अभ्यास प्रश्न:** पश्चमि एशयाई संघरष के पीछे की ऐतहासिक पृष्टभूमि की चर्चा कीजयि। वे कौन-से दृष्टिकोण हैं जनि के माध्यम से इस संघरष को हल कयिा जा सकता है?

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वरष के प्रश्न

**?????????:**

**प्रश्न.** दक्षणि-पश्चमि एशया का नमिनलखिति में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक नहीं फैला है? (2015)

- सीरया
- जॉर्डन
- लेबनान
- इजरायल

**उत्तर: (b)**

**प्रश्न.** कभी-कभी समाचारों में "टू स्टेट सॉल्यूशन" शब्द का उल्लेख कसि संदर्भ में कयिा जाता है? (2018)

- चीन
- इजराइल
- इराक
- यमन

**उत्तर: (b)**

**?????????**

**प्रश्न.** "भारत के इजरायल के साथ संबंधों ने हाल ही में एक ऐसी गहराई और वविधिता हासलि की है, जसिकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" वविचना कीजयि। (2018)